

permission of the competent authority.

(b) Seven Cameramen are reported to have accepted outside commercial work including, commercial films without obtaining the prior permission of the competent authority.

बिहार में कृषि विज्ञान केन्द्र

1303. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कुल कितने कृषि केन्द्र हैं और वे किस तरीके से कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या मुंगेर जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र में अभी भी विशेषज्ञों तथा संसाधनों की कमी है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) बरियारपुर के "बिन्दा दियारा" में इसका उप-केन्द्र स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं विशेष रूप से जबकि यह केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह कार्य कर रहे हैं लेकिन इस केन्द्र को शहरी क्षेत्रों से स्थानान्तरित नहीं किया गया है; और

(घ) क्या बिन्दा दियारा में "परवल" सब्जी पर व्यावहारिक वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य कराया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बिहार में 3 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे हैं। ये केन्द्र कार्य के विभिन्न स्तरों पर हैं जो उनकी कार्य-श्रवधि, अपने-अपने मेजबान संस्थान से प्राप्त भवनों, औजार आदि से सम्बन्धित अवस्थापन सुविधाओं और इस परियोजना के अन्तर्गत विकसित बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर करते हैं।

(ख) जी नहीं श्रीमान् ।

(ग) कृषि विज्ञान केन्द्रों के उपकेन्द्र स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं है। "बिन्दा दियारा" के किसानों के प्रशिक्षण की आवश्यकता मुंगेर के कृषि विज्ञान केन्द्र से पूरी हो सकती है।

(घ) कृषि विज्ञान केन्द्र व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाएँ हैं इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में उन्हें किसी प्रकार के अनुसंधान संबंधी अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी जाती। फिर भी, दियारा क्षेत्र में परवल के अनुसंधान संबंधी कार्यों की देख-रेख राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर द्वारा की जा रही है।

समाचार एजेंसियों को विज्ञापन तथा सहायता

1304. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी और अंग्रेजी की पृथक पृथक कौन-कौन सी समाचार एजेंसियाँ सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सूची में शामिल हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एजेंसी को कितने-कितने विज्ञापन और अन्य सहायता दी गई ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक को कितनी और किस प्रकार की सहायता दी गई ;

(घ) किन-किन समाचार एजेंसियों को दी जाने वाली सहायता कम की गई है या कम की जा रही है ;

(ङ) क्या यह सच है कि हिन्दी समाचार एजेंसियों को यह सहायता नहीं दी गयी है ; और

(च) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) समाचार एजेंसियों को सूचीबद्ध करने की कोई प्रणाली नहीं है।